Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

वैश्वीकरण के उपरांत अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) समुदाय की बहुआयामी राजनीतिक एवं आर्थिक भूमिका: एक समकालीन विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. अशोक कुमार मीना

सहायक आचार्य,राजनीति विज्ञान राजकीय महाविधालय मासलपुर,करौली, राजस्थान,भारत

Corresponding Author: * डॉ. अशोक कुमार मीना

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.22111439

सार

प्रस्तुत शोध पत्र वर्ष 1991 के आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के पश्चात् अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारतीय प्रवासियों, विशेष रूप से अनिवासी भारतीय (एनआरआई) तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) की बदलती सामाजिक, आर्थिक एवं रणनीतिक भूमिका का सर्वांगीण परीक्षण करता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रतिभा पलायन *(Brain Drain)* के रूप में देखे जाने वाले भारतीय प्रवासन को वैश्वीकरण ने प्रतिभा लाभ *(Brain Gain)* और राष्ट्रीय शक्ति संवर्धन की धुरी में रूपांतरित कर दिया है। यह शोध पत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रेषित धन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उद्यमशीलता, नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में प्रवासी भारतीयों के आर्थिक अवदान का सांख्यिकीय एवं गुणात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

साथ ही, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, भू-राजनीतिक लॉबिंग, कूटनीतिक वार्ताओं, सॉफ्ट पावर विस्तार तथा घरेलू चुनावी राजनीति में प्रवासी प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है। अध्ययन के निष्कर्ष यह स्पष्ट करते हैं कि भारतीय डायस्पोरा अब मात्र एक बाह्य दर्शक नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक पुनरुत्थान, नीति निर्माण और वैश्विक रणनीतिक सशक्तिकरण का एक अपरिहार्य एवं सक्रिय भागीदार बन चुका है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 08-07-2026
- **Accepted:** 21-08-2026
- **Published:** 26-08-2026
- **MRR:**4(8); 2026: 266-271
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

मीना अ. कु . वैश्वीकरण के उपरांत अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) समुदाय की बहुआयामी राजनीतिक एवं आर्थिक भूमिका: एक समकालीन विश्लेषणात्मक अध्ययन Indian J Mod Res Rev. 2026;4(8):266-271.

Access this Article Online

www.mrrjournal.in

मुख्य शब्द: वैश्वीकरण, अनिवासी भारतीय (एनआरआई), प्रवासी भारतीय, प्रेषित धन (रेमिटेंस), आर्थिक विकास, प्रवासी कूटनीति, लॉबिंग, सॉफ्ट पावर।

© 2026 डॉ. अशोक कुमार मीना. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

वैश्वीकरण आधुनिक विश्व व्यवस्था की सबसे प्रभावशाली परिघटना है, जिसने भौगोलिक सीमाओं को शिथिल करते हुए पूंजी, श्रम, प्रौद्योगिकी और विचारों के निर्बाध प्रवाह को संभव बनाया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, वर्ष 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीतियों—उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण (एलपीजी)—ने न केवल घरेलू अर्थव्यवस्था के ढांचे को बदला, बल्कि वैश्विक स्तर पर फैले भारतीय समुदाय और मातृभूमि के मध्य संबंधों को एक नवीन रणनीतिक आयाम भी प्रदान किया।

ऐतिहासिक रूप से, भारत से प्रवासन के तीन प्रमुख चरण रहे हैं:

1. औपनिवेशिक काल में 'गिरमिटिया' श्रमिकों का जबरन प्रवासन,
2. स्वतंत्रता के पश्चात् 1960-70 के दशकों में पश्चिमी देशों की ओर उच्च शिक्षित तकनीकी पेशेवरों का प्रस्थान, और
3. 1970 के दशक के मध्य में खाड़ी देशों की ओर अर्द्ध-कुशल तथा कुशल कामगारों का प्रवाह।

वैश्वीकरण से पूर्व, भारत से पश्चिमी देशों की ओर होने वाले उच्च-कौशल प्रवासन को राष्ट्रीय संपदा और बौद्धिक पूंजी की गंभीर क्षति माना जाता था, जिसे सामाजिक विज्ञान के विमर्श में 'प्रतिभा पलायन' (Brain Drain) कहा गया। किंतु, 1990 के दशक के बाद सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति, बहुराष्ट्रीय निगमों के उभार और उदारीकृत आर्थिक नीतियों ने इस विमर्श को पूरी तरह पलट दिया। भारतीय प्रवासियों की सफलता ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिष्ठा दिलाई और भारत सरकार ने भी अपनी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए डायस्पोरा को 'रणनीतिक संपत्ति' (Strategic Asset) के रूप में मान्यता दी।

आज 3.2 करोड़ से अधिक का भारतीय डायस्पोरा विश्व के लगभग 140 देशों में विस्तृत है। यह समुदाय वित्तीय संपदा, बौद्धिक संपदा और राजनीतिक प्रभाव—तीनों ही स्तरों पर अभूतपूर्व रूप से सशक्त हुआ है। प्रस्तुत शोध पत्र का केंद्रीय उद्देश्य वैश्वीकरण के उपरांत अनिवासी भारतीयों की भारत के प्रति आर्थिक और राजनीतिक भूमिका के विविध आयामों, चुनौतियों तथा भविष्योन्मुखी संभावनाओं का गहन विश्लेषण करना है।

2. शोध के उद्देश्य

प्रवासी भारतीयों का प्रभाव वर्तमान में केवल विदेशी मुद्रा भेजने तक सीमित नहीं रह गया है। यह द्विपक्षीय संधियों, वैश्विक व्यापार नीतियों, कूटनीतिक गठबंधनों तथा घरेलू राजनीतिक विमर्शों तक फैल चुका है। इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- वैश्वीकरण के बाद भारतीय प्रवासियों के प्रति भारत सरकार की नीतियों में आए संरचनात्मक बदलावों का विश्लेषण करना।
- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार, प्रेषित धन (रेमिटेंस), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में एनआरआई वर्ग की आर्थिक भूमिका की पड़ताल करना।
- मेजबान देशों में भारतीय प्रवासियों के राजनीतिक सशक्तिकरण, लॉबिंग क्षमताओं और भारत-केंद्रित कूटनीतिक प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- भारत की आंतरिक राजनीति, चुनावी वित्तपोषण, नीति निर्माण और बौद्धिक विमर्श में प्रवासियों के बढ़ते दखल का परीक्षण करना।
- प्रवासी निवेश और कूटनीति के मार्ग में उपस्थित प्रशासनिक, वित्तीय एवं सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियों की पहचान करते हुए नीतिगत समाधान प्रस्तावित करना।

3. शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक एवं ऐतिहासिक शोध प्रविधि पर आधारित है। इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का समन्वित उपयोग किया गया है:

- **द्वितीयक आंकड़े एवं स्रोत:** विदेश मंत्रालय (भारत सरकार), भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम), और नीति आयोग द्वारा प्रकाशित विभिन्न वार्षिक रिपोर्टें, सांख्यिकीय दस्तावेज एवं श्वेत पत्र।
- **साहित्यिक स्रोत:** प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध आलेख, संदर्भ पुस्तकें, संसदीय कार्यवाहियां और नीतिगत दस्तावेज।
- **तुलनात्मक एवं प्रासंगिक विश्लेषण:** वैश्वीकरण पूर्व (1991 से पूर्व) तथा वैश्वीकरण उपरांत (1991 से अद्यतन) प्रवासी नीतियों और उनके प्रभावों का कालानुक्रमिक व तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है।

4. नीतिगत प्रतिमान विस्थापन: उपेक्षा से रणनीतिक सहभागिता

स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशकों में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली विदेश नीति का दृष्टिकोण यह था कि विदेशों में बसे भारतीयों को अपने मेजबान देशों के साथ ही पूर्णतः एकीकृत हो जाना चाहिए और भारत सरकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस नीति ने प्रवासियों और मातृभूमि के बीच एक भावनात्मक दूरी बनाए रखी।

1990 के दशक में भुगतान संतुलन के ऐतिहासिक संकट ने भारत सरकार को विदेशी पूंजी और अनिवासी भारतीयों की वित्तीय क्षमता का वास्तविक अहसास कराया। इसके परिणामस्वरूप एक बड़ा नीतिगत प्रतिमान विस्थापन (Paradigm Shift) हुआ:

[उपेक्षा का युग: 1947–1990] ⟶ [आर्थिक संकट व पहचान: 1991–2000] ⟶ [रणनीतिक सहभागिता व सशक्तिकरण: 2000–अद्यतन]

महत्वपूर्ण नीतिगत मील के पत्थर:

1. **एल.एम. सिंघवी उच्च-स्तरीय समिति (2000):** भारत सरकार द्वारा गठित इस समिति ने डायस्पोरा से संबंध प्रगाढ़ करने का ऐतिहासिक रोडमैप तैयार किया।
2. **प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी):** वर्ष 2003 से प्रतिवर्ष (बाद में द्विवार्षिक) 9 जनवरी को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की स्मृति में इस सम्मेलन का आयोजन प्रारंभ हुआ।
3. **प्रवासी भारतीय नागरिकता (ओसीआई कार्ड प्रणाली):** अनिवासी भारतीयों और विदेशी मूल के भारतीयों को आजीवन वीजा-मुक्त यात्रा, संपत्ति अर्जन तथा आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी हेतु ओसीआई (OCI) योजना का क्रियान्वयन।

© 2026 डॉ. अशोक कुमार मीना. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

4. **संस्थागत ढांचा:** प्रवासी भारतीय मामलों के अलग मंत्रालय का गठन (जिसे बाद में विदेश मंत्रालय में समाहित कर सुदृढ़ किया गया), इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन तथा 'प्रवासी कौशल विकास योजना' जैसी पहलों का संचालन।

5. एनआरआई समुदाय की आर्थिक भूमिका

वैश्वीकरण के पश्चात अनिवासी भारतीयों ने भारत के वृहद-आर्थिक संतुलन (Macro-economic Stability) को बनाए रखने में एक ढाल के रूप में कार्य किया है।

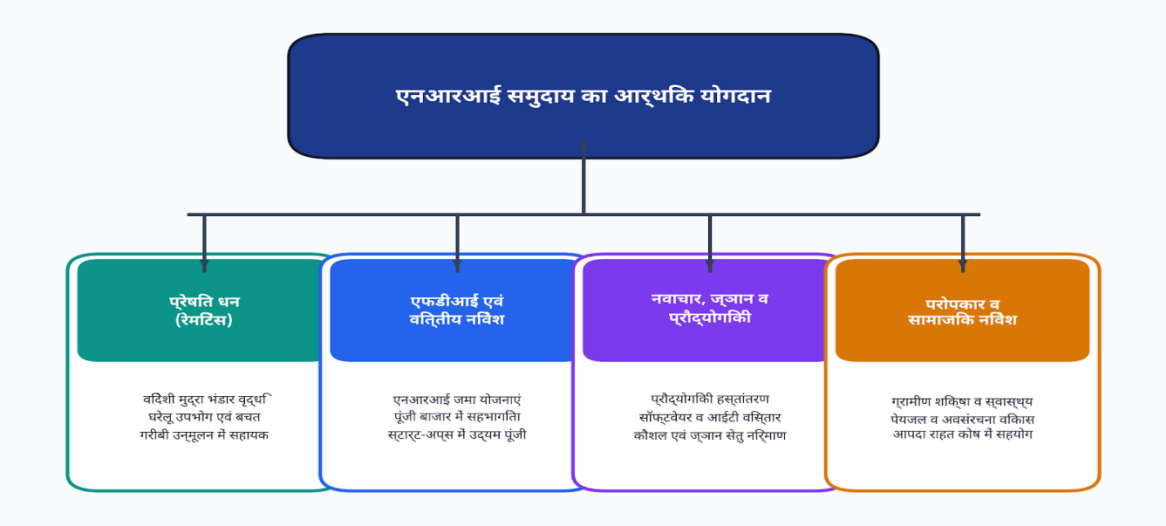

5.1 प्रेषित धन (रेमिटेंस) और विदेशी मुद्रा भंडार

विश्व बैंक के प्रवासन और विकास प्रतिवेदनों के अनुसार, भारत विश्व में प्रेषित धन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश बना हुआ है। वर्ष 1990-91 में जहां भारत को मात्र 2.1 अरब डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त होता था, वहीं वैश्वीकरण के बाद यह आंकड़ा तीव्र गति से बढ़ते हुए हाल के वर्षों में 100 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया।

दशक / वर्ष	अनुमानित वार्षिक प्रेषित धन (अमेरिकी डॉलर में)	मुख्य स्रोत क्षेत्र	प्रमुख उपयोग
1990-91	~$2.1 अरब	खाड़ी देश, यूके	घरेलू बुनियादी आवश्यकताएं, उपभोग
2000-01	~$12.8 अरब	खाड़ी क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका	जीवन स्तर सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य
2010-11	~$55.6 अरब	उत्तरी अमेरिका, खाड़ी, यूरोप	अचल संपत्ति, बैंक बचत, उपभोग
समकालीन	~$110+ अरब	यूएसए, यूएई, यूके, सिंगापुर	उपभोग, स्वास्थ्य, पूंजी निर्माण, स्टार्ट-अप्स

रेमिटेंस का आर्थिक प्रभाव:

- **चालू खाता घाटे (CAD) की भरपाई:** प्रेषित धन भारत के व्यापार घाटे को संतुलित करने और विदेशी मुद्रा भंडार को स्थायित्व देने में निर्णायक भूमिका निभाता है।
- **ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास:** केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रेमिटेंस ने गरीबी उन्मूलन, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और उच्च शिक्षा के वित्तपोषण में क्रांति ला दी है।

5.2 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और पूंजी बाजार में भागीदारी

अनिवासी भारतीय केवल पारिवारिक स्तर पर धन नहीं भेजते, बल्कि भारत के पूंजी बाजार और बुनियादी ढांचे में भी संस्थागत निवेशक के रूप में उभरे हैं:

- **एनआरआई जमा योजनाएं:** विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) तथा अनिवासी बाह्य (एनआरई) खातों के माध्यम से भारतीय बैंकों में भारी मात्रा में तरलता का प्रवाह होता है।
- **संकट मोचन की भूमिका:** जब भी भारत ने गंभीर आर्थिक या भू-राजनीतिक प्रतिबंधों (जैसे 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद के प्रतिबंध) का सामना किया, भारत सरकार द्वारा जारी 'रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स' (1998) और 'इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट्स' (2000) को एनआरआई समुदाय ने भारी समर्थन देकर विदेशी मुद्रा का अभूतपूर्व संकट टाला।
- **उद्यम पूंजी और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र:** सिलिकॉन वैली (अमेरिका) और लंदन में कार्यरत भारतीय मूल के निवेशकों ने भारत के स्टार्ट-अप क्रांति (बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम) में एंजेल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में खरबों रुपये का निवेश किया है।

5.3 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नवोन्मेष और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था

भारतीय प्रवासियों ने पश्चिमी देशों में सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और वित्तीय सेवाओं में नेतृत्वकारी पदों पर पहुंचकर 'ज्ञान सेतु' (Knowledge Bridge) का निर्माण किया:

© 2026 डॉ. अशोक कुमार मीना. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

- **सॉफ्टवेयर एवं सेवा क्षेत्र का विकास:** इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी भारतीय कंपनियों के वैश्विक विस्तार में विदेशों में कार्यरत प्रवासी भारतीय अधिकारियों ने अनुबंध, नेटवर्किंग और तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराई।
- **'ब्रेन सर्कुलेशन' (BRAIN CIRCULATION):** उच्च शिक्षित पेशेवर अब विदेशों से अनुभव और पूंजी लेकर भारत लौट रहे हैं तथा यहां नवाचारी अनुसंधान केंद्रों, फिनटेक कंपनियों और वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) की स्थापना कर रहे हैं।

5.4 सामाजिक परोपकार (Diaspora Philanthropy)

प्रवासी भारतीयों ने भारत के सामाजिक क्षेत्र में भी भारी योगदान दिया है। ग्रामीण विद्यालयों का आधुनिकीकरण, सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों का निर्माण (उदा. गुजरात और आंध्र प्रदेश के चैरिटेबल ट्रस्ट), पेयजल परियोजनाएं और आपदा राहत कोषों में प्रवासियों का योगदान अभूतपूर्व रहा है।

6. एनआरआई समुदाय की राजनीतिक भूमिका

वैश्वीकरण ने आर्थिक शक्ति के साथ-साथ प्रवासियों को राजनीतिक चेतना और प्रभावशीलता भी प्रदान की है। यह राजनीतिक भूमिका दो प्रमुख स्तरों पर परिलक्षित होती है: **अंतरराष्ट्रीय/मेजबान देश स्तर पर** और **घरेलू भारतीय राजनीति के स्तर पर**।

6.1 मेजबान देशों में रणनीतिक लॉबिंग और भू-राजनीतिक प्रभाव

वैश्विक स्तर पर भारतीय समुदाय ने अपनी जनसांख्यिकीय शक्ति को संगठित राजनीतिक दबाव समूहों (Lobby Groups) में रूपांतरित किया है:

- **भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता (2008):** अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय (विशेषकर 'यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल' और विभिन्न हिंदू-भारतीय संगठनों) ने अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों पर द्विदलीय दबाव बनाकर इस ऐतिहासिक समझौते को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह प्रवासी लॉबिंग की सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय मानी जाती है।
- **राष्ट्रीय हितों की रक्षा:** कश्मीर मुद्दे, सीमा पार आतंकवाद, और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि के विरुद्ध होने वाले दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए प्रवासी समूह मेजबान देशों की संसदों और मीडिया मंचों पर प्रभावी पैरवी करते हैं।
- **मेजबान देशों की मुख्यधारा की राजनीति में प्रवेश:** अमेरिका (संसद, सीनेट और राष्ट्रपति प्रशासन), यूनाइटेड किंगडम (संसद और मंत्रिमंडल), कनाडा, सिंगापुर, मॉरीशस और यूरोपीय देशों में भारतीय मूल के नेताओं की बढ़ती उपस्थिति भारत के साथ उनके देशों के द्विपक्षीय संबंधों को एक सकारात्मक और रणनीतिक आधार प्रदान करती है।

6.2 सॉफ्ट पावर (सांस्कृतिक शक्ति) का वैश्विक प्रसार

जोसेफ नाई की 'सॉफ्ट पावर' संकल्पना के आलोक में, प्रवासी भारतीय भारत के सबसे प्रभावी 'सांस्कृतिक राजदूत' हैं:

- **योग और आयुर्वेद:** अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) की वैश्विक स्वीकार्यता और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने में डायस्पोरा की केंद्रीय भूमिका रही है।
- **सिनेमा, कला और खानपान:** भारतीय सिनेमा (बॉलीवुड), संगीत, शास्त्रीय नृत्य और भारतीय व्यंजनों ने वैश्विक जनमानस में भारत के प्रति आकर्षण और सद्भावना (Goodwill) पैदा की है।
- **शैक्षणिक और बौद्धिक प्रभाव:** वैश्विक विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और बहुपक्षीय संगठनों (जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ) में भारतीय मूल के विद्वानों का आधिपत्य भारत के विमर्श को अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक जगत में प्रतिष्ठा दिलाता है।

6.3 भारत की घरेलू राजनीति और चुनावी प्रक्रियाओं में प्रभाव

वैश्वीकरण और डिजिटल संचार क्रांति (सोशल मीडिया) ने प्रवासियों को भारत की आंतरिक राजनीति में सीधे हस्तक्षेप और भागीदारी का अवसर प्रदान किया है:

- **मतदान अधिकार और कानूनी सुधार:** जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधनों के माध्यम से अनिवासी भारतीयों को मतदाता सूची में पंजीकरण का अधिकार प्राप्त हुआ है। वर्तमान में प्रॉक्सी वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक डाक मतपत्र (ईटीपीबीएस) के माध्यम से मतदान की सुविधा पर गंभीर नीतिगत विमर्श जारी है।
- **चुनावी अभियान और वित्तपोषण:** प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों ने विदेशों में अपनी औपचारिक शाखाएं (जैसे 'ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी', 'इंडियन ओवरसीज कांग्रेस' आदि) स्थापित की हैं। ये शाखाएं चुनावों के दौरान धन जुटाने, सोशल मीडिया अभियानों को संचालित करने और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए 'फोन-बैंकिंग' जैसे अभियान चलाती हैं।
- **नीति निर्धारण में प्रत्यक्ष परामर्श:** भारत सरकार विभिन्न थिंक टैंकों (जैसे नीति आयोग, भारतीय वैश्विक परिषद) के माध्यम से एनआरआई विशेषज्ञों से आर्थिक सुधारों, उच्च शिक्षा नीति और शहरी विकास योजनाओं पर नियमित परामर्श लेती है।

7. तुलनात्मक विश्लेषण: वैश्वीकरण पूर्व एवं पश्चात

मापदंड	वैश्वीकरण पूर्व युग (1947–1990)	वैश्वीकरण उपरांत युग (1991–अद्यतन)
प्रवासन का स्वरूप	प्रतिभा पलायन (Brain Drain) और वित्तीय क्षति	प्रतिभा लाभ (Brain Gain) और रणनीतिक पूंजी
सरकारी दृष्टिकोण	तटस्थता, उपेक्षा और दूरस्थ संबंध	सक्रिय जुड़ाव, संस्थागत सम्मान और भागीदारी
वित्तीय प्रवाह	अल्प प्रेषित धन, अनौपचारिक माध्यम (हवाला आदि)	$100+ अरब से अधिक औपचारिक रेमिटेंस और भारी एफडीआई
राजनीतिक प्रभाव	मेजबान देशों में राजनीतिक रूप से असंगठित	शक्तिशाली लॉबी समूह, नीति निर्माता और निर्वाचित प्रतिनिधि
सॉफ्ट पावर प्रभाव	सीमित, स्थानीय स्तर तक सीमित सांस्कृतिक प्रभाव	योग, तकनीक, सिनेमा और कूटनीति के माध्यम से वैश्विक आधिपत्य
कानूनी स्थिति	दोहरी नागरिकता या विशेष दर्जे का पूर्ण अभाव	ओसीआई (OCI) कार्ड, दीर्घकालिक वीजा और संपत्ति अधिकार

© 2026 डॉ. अशोक कुमार मीना. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

8. प्रमुख चुनौतियां एवं समस्याएं

प्रवासी भारतीयों के अपार योगदान के बावजूद, भारत-डायस्पोरा संबंधों के मार्ग में कई गंभीर चुनौतियां विद्यमान हैं:

1. **प्रशासनिक जटिलताएं और नौकरशाही अवरोध:** भारत में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों को जटिल नियामक प्रक्रियाओं, कराधान संबंधी अस्पष्टताओं, भूमि अधिग्रहण की बाधाओं और विधिक विवादों में विलंब का सामना करना पड़ता है।
2. **खाड़ी बनाम पश्चिमी प्रवासियों में संरचनात्मक विषमता:**

- पश्चिमी देशों में रहने वाले प्रवासी मुख्य रूप से श्वेत-कॉलर (White-collar) पेशेवर हैं, जो नागरिकता और राजनीतिक अधिकारों का उपभोग करते हैं।
- इसके विपरीत, खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों में रहने वाले लगभग 90 लाख भारतीय कामगार नीले-कॉलर (Blue-collar) श्रमिक हैं। उन्हें न तो वहां नागरिकता मिलती है और न ही पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा। संकट के समय (जैसे युद्ध या महामारी) उनके पुनर्वास की भारी चुनौती भारत सरकार के समक्ष उत्पन्न होती है।

3. **घरेलू राजनीति का ध्रुवीकरण और विदेशों में विभाजन:** भारत के आंतरिक राजनीतिक, वैचारिक और धार्मिक विभाजन अब विदेशों में बसे डायस्पोरा में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं, जिससे मेजबान देशों में भारतीय समुदाय की सामूहिक एकता और लॉबिंग क्षमता कमजोर होती है।
4. **मेजबान देशों में संप्रभुता संबंधी संवेदनशीलता:** विदेशों में अत्यधिक आक्रामक घरेलू राजनीतिक रैलियों और लॉबिंग के कारण मेजबान देशों की सरकारें कभी-कभी इसे अपनी घरेलू राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप के रूप में देखने लगती हैं।

9. भविष्य की राह एवं नीतिगत सुझाव

भारत को अपनी 2047 तक 'विकसित भारत' की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रवासी भारतीयों की क्षमता का और अधिक व्यवस्थित दोहन करना होगा। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:

- **प्रवासी निवेश संवर्धन हेतु सिंगल विंडो सिस्टम:** एनआरआई निवेशकों के लिए एक समर्पित, तीव्र और विवाद-रहित डिजिटल सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम का निर्माण किया जाए, जो विशेषकर एमएसएमई और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करे।
- **खाड़ी कामगारों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा छत्र:** खाड़ी देशों से लौटने वाले श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय पुनर्वास नीति, पेंशन योजना और कौशल प्रमाणीकरण व्यवस्था बनाई जाए।
- **प्रॉक्सी या डिजिटल मतदान की सुरक्षित व्यवस्था:** चुनाव आयोग को सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए अनिवासी भारतीयों के लिए सुगम एवं प्रामाणिक डिजिटल अथवा पोस्टल मतदान प्रणाली को शीघ्र लागू करना चाहिए।
- **अनुसंधान एवं विकास (R&D) में डायस्पोरा लिंकेज:** भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों (आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विश्वविद्यालय) को विदेशों में कार्यरत शीर्ष भारतीय शोधकर्ताओं के साथ संयुक्त शोध, फैकल्टी एक्सचेंज और पेटेंट विकास हेतु दीर्घकालिक वित्तीय अनुदान देना चाहिए।
- **दूसरी और तीसरी पीढ़ी के प्रवासियों का जुड़ाव:** भारतवंशी युवाओं को भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति से जोड़ने के लिए 'भारत को जानो' (Know India) जैसे कार्यक्रमों को और अधिक व्यापक, तकनीकी-युक्त और आकर्षक बनाया जाए।

10. निष्कर्ष

वैश्वीकरण के पश्चात अनिवासी भारतीय (एनआरआई) समुदाय भारत के आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का एक अनिवार्य स्तंभ बनकर उभरा है। 1991 के बाद की अवधि ने यह सिद्ध कर दिया है कि डायस्पोरा अब भारत के लिए केवल विदेशी मुद्रा का स्रोत नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली भू-राजनीतिक शक्ति, ज्ञान का भंडार और सांस्कृतिक राजदूत है।

आर्थिक मोर्चे पर जहां प्रेषित धन और निवेश ने देश की वित्तीय स्थिरता को संबल दिया है, वहीं राजनीतिक मोर्चे पर वैश्विक लॉबिंग और सॉफ्ट पावर ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के रणनीतिक कद को ऊंचा किया है। यद्यपि प्रशासनिक जटिलताओं, कामगारों के कल्याण और वैचारिक विभाजनों जैसी चुनौतियां विद्यमान हैं, किंतु एक सुविचारित, समावेशी और भविष्योन्मुखी राष्ट्रीय प्रवासी नीति के माध्यम से भारत अपने डायस्पोरा के साथ संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है, जो 21वीं सदी में भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल SP. वैश्वीकरण, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन एवं भारतीय अर्थव्यवस्था. नई दिल्ली: विश्वविद्यालय प्रकाशन; 2018.
2. कपाड़िया KM. भारतीय समाज में परिवर्तन और प्रवासी समुदाय की भूमिका. जयपुर: रावत पब्लिकेशंस; 2015.
3. कुमार सतीश. भारत की विदेश नीति और प्रवासी कूटनीति: नए आयाम. नई दिल्ली: तक्षशिला अध्ययन केंद्र; 2020.
4. खुराना RK. प्रवासी भारतीय और विदेशी मुद्रा भंडार: एक अर्थशास्त्रीय विश्लेषण. आर्थिक समीक्षा. 2017;42(3):112-128.
5. गुप्ता अनुपम. भारत-अमेरिका संबंध और भारतीय लॉबी का प्रभाव. भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका. 2019;31(2):45-62.
6. जोशी PC. सॉफ्ट पावर और भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रसार. दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी; 2016.
7. झा नलिन. वैश्वीकरण के दौर में डायस्पोरा कूटनीति. अंतरराष्ट्रीय संबंध त्रैमासिक. 2021;18(1):78-95.
8. त्रिपाठी अमरेश. खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिक: सुरक्षा, चुनौतियां एवं नीतियां. लखनऊ: उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान; 2022.
9. थारूर शशि. पॉक्स इंडिका: इक्कीसवीं सदी में भारत और विश्व. नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स इंडिया; 2013.
10. दीवान विकास. उदारीकरण के पश्चात भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और एनआरआई पूंजी. योजना. 2019;63(8):24-29.
11. नीति आयोग. भारत में नवाचार और प्रवासी प्रतिभा की सहभागिता: नीतिगत दस्तावेज. नई दिल्ली: नीति आयोग, भारत सरकार; 2023.

© 2026 डॉ. अशोक कुमार मीना. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

12. पंत HV. समकालीन भारतीय विदेश नीति के रणनीतिक आयाम. नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान; 2021.
13. पाठक विमलेश. प्रतिभा पलायन से प्रतिभा लाभ: भारतीय आईटी पेशेवरों का अध्ययन. समाजशास्त्र और विकास. 2018;14(2):205-220.
14. बजाज रमेश. भारतीय डायस्पोरा: इतिहास, राजनीति और आर्थिकी. नई दिल्ली: कनिष्क पब्लिशर्स; 2016.
15. भारतीय रिजर्व बैंक. अनिवासी जमा और प्रेषित धन पर वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट. मुंबई: रिजर्व बैंक बुलेटिन; 2022.
16. मिश्रा राजेश. अनिवासी भारतीयों के मतदान अधिकार: संवैधानिक और व्यावहारिक पहलू. लोकतंत्र एवं शासन जर्नल. 2020;12(4):150-168.
17. विदेश मंत्रालय. भारतीय डायस्पोरा पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट (सिंघवी समिति रिपोर्ट). नई दिल्ली: भारत सरकार; 2001.
18. विदेश मंत्रालय. प्रवासी भारतीय दिवस एवं द्विपक्षीय संबंध वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23. नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय, भारत सरकार; 2023.
19. विश्व बैंक. प्रवासन और विकास संक्षिप्त विवरण (माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 38). वाशिंगटन डी.सी.: विश्व बैंक समूह; 2023.
20. शर्मा कौशल किशोर. अंतरराष्ट्रीय राजनीति और प्रवासी दबाव समूह. नई दिल्ली: अनामिका पब्लिशर्स; 2017.
21. सिंह आनंद. सिल्क रूट से सिलिकॉन वैली: भारतीय प्रवासन का महागाथा. वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन; 2019.
22. सक्सेना वंदना. प्रवासी भारतीयों का लोकोपकारी योगदान और ग्रामीण विकास. कुरुक्षेत्र. 2021;67(5):33-38.
23. सेन अमर्त्य. पहचान और हिंसा: तकदीर का भ्रम. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन; 2006.
24. श्रीवास्तव धीरज. वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का उभरता प्रभाव और अनिवासी भारतीय. वाणिज्य एवं व्यापार पत्रिका. 2020;29(1):88-103.

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the Author

डॉ. अशोक कुमार मीना राजकीय महाविद्यालय मासलपुर, करौली, राजस्थान में राजनीति विज्ञान विषय के सहायक आचार्य हैं। उनकी शैक्षणिक रुचि भारतीय राजनीति, शासन एवं लोक प्रशासन के अध्ययन में केंद्रित है। वे विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध हैं तथा राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्यों में सक्रिय योगदान देते रहे हैं।

© 2026 डॉ. अशोक कुमार मीना. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/